Impact Factor (SJIF): 5.158 E-ISSN: 2583-7206

International Journal of All Subject Research

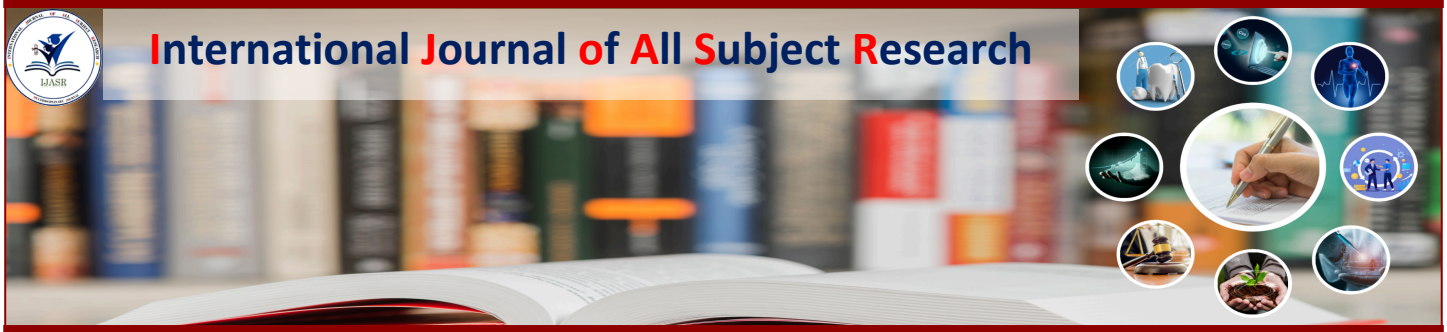

Received: 22/April/2024 IJASR: 2024; 3(3):13-17 Accepted: 28/May/2024

भारत और बांग्लादेश में आर्थिक विकास पर द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का प्रभाव

[*1]Ajay Pratap Singh and [2]Dr. Pappi Misra

[*1]Research Scholar, Department of Political Science, D.G. PG College Kanpur, Uttar Pradesh, India.

[2]Professor, Department of Political Science, D.G. PG College Kanpur, Uttar Pradesh, India.

सारांश

यह शोधपत्र 21वीं सदी में भारत और बांग्लादेश के आर्थिक विकास पर द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के प्रभाव की जांच करता है। 1980 के व्यापार समझौते, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) और अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल (PIWTT) जैसे प्रमुख व्यापार समझौतों के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से, अध्ययन दोनों देशों में व्यापार की मात्रा, जीडीपी वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और रोजगार बढ़ाने में उनकी भूमिका की जांच करता है। निष्कर्ष बताते हैं कि इन समझौतों ने निर्यात के अवसरों को बढ़ाकर, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर और रोजगार पैदा करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्यापार असंतुलन, गैर-टैरिफ बाधाओं और राजनीतिक तनाव जैसी चुनौतियों के बावजूद, शोधपत्र आर्थिक विविधीकरण, क्षेत्रीय एकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के अवसरों पर प्रकाश डालता है। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लाभों को अनुकूलित करने, भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर आर्थिक विकास और मजबूत आर्थिक संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रदान की गई हैं।

मुख्य शब्द: द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreements), आर्थिक वृद्धि (Economic Growth), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment), व्यापार मात्रा (Trade Volume), सीमा हाट (Border Haats) I

प्रस्तावना

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से काफी विकास हुआ है। साझा इतिहास, संस्कृति और आर्थिक हितों में निहित, दोनों राष्ट्रों ने विभिन्न द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने आर्थिक सहयोग को लगातार गहरा करने की कोशिश की है। ये समझौते व्यापार संबंधों को बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं। यह शोधपत्र 21वीं सदी में भारत और बांग्लादेश के आर्थिक विकास पर ऐसे व्यापार समझौतों के प्रभाव पर गहराई से चर्चा करता है, जिसमें प्रमुख समझौतों, व्यापार की मात्रा, आर्थिक संकेतकों और नीतिगत निहितार्थों की जांच की गई है।

ऐतिहासिक रूप से, भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने आपसी समर्थन और सहयोग की विशेषता वाले संबंधों की नींव रखी। संरचित आर्थिक संबंधों की दिशा में सबसे शुरुआती औपचारिक कदमों में से एक 1980 का व्यापार समझौता था। इस समझौते का उद्देश्य टैरिफ को कम करना और दोनों देशों के बीच व्यापार प्रवाह को सुगम बनाना था। पिछले कुछ वर्षों में, व्यापार समझौतों का दायरा और गहराई बढ़ी है, जो भारत और बांग्लादेश की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं और बढ़ती परस्पर निर्भरता को दर्शाता है।

द्विपक्षीय व्यापार समझौते व्यापार बाधाओं को दूर करने, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में काम करते हैं। इस तरह के समझौतों में आम तौर पर टैरिफ में कटौती, व्यापार सुविधा उपाय, निवेश सुरक्षा और विवाद समाधान तंत्र सहित विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। भारत और बांग्लादेश के लिए, इन समझौतों ने व्यापार की मात्रा बढ़ाने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को कई प्रमुख समझौतों द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें 1980 का व्यापार समझौता, प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल (PIWTT) और सीमा हाट पहल शामिल हैं।

1980 के व्यापार समझौते ने संरचित व्यापार संबंधों के लिए एक आधार स्थापित किया, टैरिफ में कटौती और व्यापार सुविधा के माध्यम से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया। प्रस्तावित CEPA का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को और गहरा करना है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और आर्थिक सहयोग में व्यापार शामिल है। PIWTT परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, व्यापार संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और परिवहन लागत को कम करता है। इसके

***Corresponding Author:** Ajay Pratap Singh

अतिरिक्त, बॉर्डर हाट पहल, जो भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थानीय बाज़ार स्थापित करती है, स्थानीय समुदायों के बीच व्यापार को बढ़ावा देती है, आजीविका को बढ़ाती है और जमीनी स्तर पर सीमा पार आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देती है।

इस पत्र का उद्देश्य कई उद्देश्यों को संबोधित करके भारत और बांग्लादेश के आर्थिक विकास पर इन द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के प्रभाव का विश्लेषण करना है। सबसे पहले, यह पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा में हुए बदलावों की जांच करता है, रुझानों और व्यापार समझौतों से लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करता है। दूसरे, यह दोनों देशों में जीडीपी वृद्धि, एफडीआई प्रवाह और रोजगार दरों जैसे आर्थिक संकेतकों पर इन समझौतों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। तीसरा, यह व्यापार समझौतों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों की पहचान करता है। अंत में, यह इन चुनौतियों का समाधान करने और सतत आर्थिक विकास के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लाभों को अनुकूलित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।

द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का अवलोकन

1980 का व्यापार समझौता: 1980 का व्यापार समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस समझौते ने संरचित व्यापार संबंधों की नींव रखी, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच व्यापार प्रवाह को बढ़ाना था। इस समझौते में कई तरह के सामानों पर टैरिफ कम करने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापार विवादों को हल करने के लिए तंत्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। व्यापार बाधाओं को कम करके, समझौते ने व्यापार की मात्रा में वृद्धि की, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख क्षेत्रों को लाभ हुआ। भारत के लिए, इसने अपने औद्योगिक और कृषि उत्पादों के लिए एक उभरता हुआ बाजार खोल दिया, जबकि बांग्लादेश के लिए, इसने अपने कपड़ा और जूट निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण आउटलेट प्रदान किया। 1980 के व्यापार समझौते ने गहन आर्थिक एकीकरण के लिए मंच तैयार किया और द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने के उद्देश्य से बाद के समझौतों का मार्ग प्रशस्त किया।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA): प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले समझौतों के विपरीत, जो मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित थे, CEPA का उद्देश्य सेवाओं में व्यापार, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग सहित व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करना है। यह समझौता आर्थिक संपर्क के लिए एक अधिक व्यापक ढांचा बनाने, गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने, निवेशों की रक्षा करने और पेशेवरों और श्रमिकों की सुगम आवाजाही को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। सेवाओं और निवेश को शामिल करके, CEPA का उद्देश्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते क्षेत्रों, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का लाभ उठाना है। इस समझौते से प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, नवाचार को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देगा।

अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल (PIWTT): अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल (PIWTT) एक महत्वपूर्ण समझौता है जो भारत और बांग्लादेश के बीच परिवहन और व्यापार के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। भौगोलिक निकटता और दोनों देशों द्वारा साझा की जाने वाली नदियों के व्यापक नेटवर्क को देखते हुए यह प्रोटोकॉल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देकर, PIWTT का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना और परिवहन का एक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीका प्रदान करना है। प्रोटोकॉल निर्दिष्ट नदी मार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही की अनुमति देता है, जिससे भीड़भाड़ वाले भूमि मार्गों को दरकिनार किया जा सकता है और रसद संबंधी चुनौतियों को कम किया जा सकता है। यह समझौता व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने में सहायक रहा है, खासकर सीमेंट, कोयला और खाद्यान्न जैसी थोक वस्तुओं के लिए। इसके अतिरिक्त, PIWTT ने क्षेत्रीय व्यापार को सुगम बनाया है, जिससे नदी के किनारे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को लाभ हुआ है।

सीमा हाट पहल (Border Haats Initiative): सीमा हाट पहल जमीनी स्तर पर सीमा पार व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा और अभिनव दृष्टिकोण है। सीमा हाट भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थापित स्थानीय बाजार हैं, जहां दोनों पक्षों के व्यापारी जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की आवश्यकता के बिना अपना माल बेच सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य आजीविका को बढ़ाना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और सीमा समुदायों के बीच लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। सीमा हाट छोटे व्यापारियों और कारीगरों को नए बाजारों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इस पहल को स्थानीय समुदायों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान दे रही है। व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच सीधे संपर्क को सुगम बनाकर, सीमा हाट विश्वास और आपसी समझ बनाने में मदद करते हैं, जिससे व्यापक द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते हैं।

सहयोग के उभरते क्षेत्र: इन प्रमुख समझौतों के अलावा, भारत और बांग्लादेश अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था में पहल जोर पकड़ रही है। दोनों देश सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षय ऊर्जा की क्षमता को पहचानते हैं और सौर और पवन ऊर्जा में संयुक्त परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। सड़क, रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी सहित बुनियादी ढांचे का विकास एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां दोनों देश क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था, जिसमें ई-कॉमर्स, फिनटेक और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं, दोनों देशों में तकनीकी प्रगति और बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाते हुए सहयोग के नए अवसर प्रस्तुत करती है। सहयोग के ये उभरते क्षेत्र भारत-बांग्लादेश आर्थिक संबंधों की गतिशील और विकसित प्रकृति को उजागर करते हैं, जिसका लक्ष्य साझा समृद्धि और सतत विकास हासिल करना है।

व्यापार मात्रा और आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण

व्यापार मात्रा: भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार मात्रा में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2000 में, कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.4 बिलियन डॉलर था। यह आँकड़ा काफी बढ़ गया है, हाल के वर्षों में यह 10 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। भारत से बांग्लादेश को किए जाने वाले प्रमुख निर्यातों में कृषि उत्पाद, मशीनरी, रसायन और वस्त्र शामिल हैं। इसके विपरीत, बांग्लादेश मुख्य रूप से भारत को वस्त्र, चमड़े के सामान और समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यात करता है। व्यापार मात्रा में वृद्धि का श्रेय द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को दिया जा सकता है, जिन्होंने टैरिफ को कम किया है, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और व्यापार सुविधा उपायों को बढ़ाया है। इन समझौतों ने व्यापार के लिए नए क्षेत्र भी खोले हैं, जिससे दोनों देशों में व्यापार पोर्टफोलियो के विविधीकरण में योगदान मिला है।

तालिका 1: व्यापार मात्रा और आर्थिक संकेत

Year	Total Trade Volume ($ Billion)
2000	1.4
2005	2.5
2010	2.9
2015	6.0
2020	9.5
2023	10.2

Source: *Ministry of Commerce, Government of India*

जीडीपी वृद्धि: द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का दोनों देशों की जीडीपी वृद्धि पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिसका आंशिक कारण बांग्लादेश के साथ बढ़ा हुआ व्यापार है। समझौतों ने बांग्लादेश के बाजार तक पहुंच को सुगम बनाया है, जिससे विनिर्माण, कृषि और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान मिला है। इसी तरह, बांग्लादेश ने अपने संपन्न कपड़ा और परिधान उद्योग द्वारा संचालित मजबूत जीडीपी वृद्धि का अनुभव किया है, जिसे भारतीय बाजार तक पहुंच से लाभ मिलता है। व्यापार में वृद्धि ने बांग्लादेश में औद्योगिक विकास और आर्थिक विविधीकरण को भी बढ़ावा दिया है।

तालिका 2: जीडीपी वृद्धि

Year	India GDP Growth (%)	Bangladesh GDP Growth (%)
2000	5.5	5.3
2005	7.0	6.5
2010	10.3	6.1
2015	8.0	6.6
2020	4.0	5.2
2023	6.5	6.9

Source: *Reserve Bank of India (RBI) & Bangladesh Bank*

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई): भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। द्विपक्षीय व्यापार समझौतों ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई आकर्षित हुआ है। भारत में, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बांग्लादेशी कंपनियों से निवेश में वृद्धि देखी गई है। इसके विपरीत, बांग्लादेश में भारतीय निवेश ने मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और ऊर्जा क्षेत्र को लक्षित किया है। एफडीआई में वृद्धि ने दोनों देशों में आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और रोजगार सृजन में योगदान दिया है।

तालिका 3: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

Year	FDI Inflows to India ($ Billion)	FDI Inflows to Bangladesh ($ Billion)
2000	2.3	0.5
2005	7.6	1.0
2010	24.6	1.4
2015	44.5	2.2
2020	50.0	2.6
2023	58.0	3.1

Source: *Reserve Bank of India (RBI) & Bangladesh Bank*

रोजगार के रुझान (Employment Trends): भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि का दोनों देशों में रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कपड़ा, विनिर्माण और सेवाओं जैसे उद्योगों में वृद्धि ने कई रोजगार अवसर पैदा किए हैं। भारत में, बांग्लादेश के साथ बढ़े हुए व्यापार ने कृषि, कपड़ा और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन का समर्थन किया है। बांग्लादेश में, कपड़ा और परिधान उद्योग, जो भारत को निर्यात करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है, ने रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। रोजगार में वृद्धि ने दोनों देशों में गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार में योगदान दिया है।

तालिका 4: रोजगार के रुझान (Employment Trends)

Year	Employment in India (Million)	Employment in Bangladesh (Million)
2000	400	45
2005	450	55
2010	500	60
2015	530	65
2020	560	70
2023	580	75

Source: *National Sample Survey Office (NSSO), India & Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)*

व्यापार समझौतों को लागू करने में चुनौतियाँ और अवसर

चुनौतियाँ: भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को लागू करना अपनी चुनौतियों से रहित नहीं रहा है। प्राथमिक मुद्दों में से एक व्यापार असंतुलन है, जहाँ भारत लगातार एक महत्वपूर्ण व्यापार अधिशेष का आनंद लेता है। यह असंतुलन आर्थिक और राजनीतिक संवेदनशीलताएँ पैदा करता है, बांग्लादेश इस असमानता को दूर करने के लिए भारतीय बाज़ार तक अधिक पहुँच की माँग करता है। इसके अतिरिक्त, कठोर सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ, विनियामक मानक और रसद संबंधी अड़चनें जैसी गैर-टैरिफ बाधाएँ महत्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। ये बाधाएँ व्यापार में देरी कर सकती हैं और लागत बढ़ा सकती हैं, जिससे समझौतों के माध्यम से प्राप्त टैरिफ कटौती के लाभों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, सीमा विवाद और सीमा पार आतंकवाद सहित राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ व्यापार प्रवाह को बाधित कर सकती हैं और द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। एक अन्य चुनौती अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा है, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों और पारगमन मार्गों में, जो कुशल व्यापार और परिवहन में बाधा डालता है। अंत में, सुचारू व्यापार की सुविधा और व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत को कम करने के लिए मानकों और विनियमों के अधिक संरेखण और सामंजस्य की आवश्यकता है।

अवसर: इन चुनौतियों के बावजूद, भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के कई अवसर हैं। बांग्लादेश से भारत को निर्यात को बढ़ावा देकर व्यापार असंतुलन को संबोधित करने से अधिक संतुलित और टिकाऊ व्यापार संबंध बन सकते हैं। दोनों देश मानकों की पारस्परिक मान्यता, सुव्यवस्थित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और बेहतर विनियामक सहयोग के माध्यम से गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने की दिशा में काम कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों और पारगमन मार्गों में, व्यापार दक्षता को काफी बढ़ा सकता है और लागत कम कर सकता है। सड़क, रेल और बंदरगाह विकास जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में संयुक्त निवेश से कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) और बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक

सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) जैसे क्षेत्रीय ढाँचों का लाभ उठाने से व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण और स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। एक और अवसर उभरते क्षेत्रों जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग का विस्तार करने में निहित है, जो नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है। सीमा हाट और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसी पहलों के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देकर, दोनों देश विश्वास और आपसी समझ का निर्माण कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। इन अवसरों का, यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, तो भारत और बांग्लादेश के बीच अधिक मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक संबंध बन सकते हैं।

नीतिगत अनुशंसाएँ: व्यापार समझौतों की प्रभावशीलता को बढ़ाना-

व्यापार असंतुलन को संबोधित करना

नीति निर्माताओं को भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को संतुलित करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे निम्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है:

- बांग्लादेश से निर्यात को बढ़ावा देना: कर लाभ और सुव्यवस्थित आयात प्रक्रियाओं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके भारतीय व्यवसायों को बांग्लादेश से अधिक आयात करने के लिए प्रोत्साहित करें। कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़े हुए आयात के लिए लक्षित किया जा सकता है।
- बांग्लादेशी एसएमई का समर्थन करना: बांग्लादेश में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को भारत में निर्यात करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करें।

गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना

सुचारू व्यापार प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए, नीति निर्माताओं को गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने पर काम करना चाहिए:

- मानकों का सामंजस्य: अनुपालन लागत और देरी को कम करने के लिए मानकों और प्रमाणन के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते स्थापित करें।
- सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना: माल की आवाजाही में तेजी लाने के लिए सीमा चौकियों पर संयुक्त सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और एकल-खिड़की निकासी प्रणालियों को लागू करें।
- विनियामक सहयोग में सुधार: विनियमों को संरेखित करने और व्यापार मुद्दों को तेजी से हल करने के लिए विनियामक निकायों के बीच नियमित संवाद।

बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

कुशल व्यापार के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण है। नीति निर्माताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए:

- सीमा बुनियादी ढांचे का विकास: बेहतर सड़कें, गोदाम और सीमा शुल्क सुविधाओं सहित सीमा पार करने की सुविधाओं में सुधार।
- पारगमन मार्गों का उन्नयन: परिवहन लागत और समय को कम करने के लिए दोनों देशों में प्रमुख व्यापार केंद्रों को जोड़ने वाले रेल और सड़क नेटवर्क को उन्नत करने में निवेश करें।
- संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देना: बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स पार्कों जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करें जो दोनों देशों को लाभान्वित करते हैं।

क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना

क्षेत्रीय ढांचे का लाभ उठाने से द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लाभों को बढ़ाया जा सकता है:

- क्षेत्रीय पहलों में शामिल होना: क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सार्क और बिम्सटेक पहलों में सक्रिय रूप से भाग लें।
- क्षेत्रीय परियोजनाओं पर सहयोग करना: ऊर्जा ग्रिड और परिवहन गलियारों जैसी क्षेत्रीय परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से काम करें, जो क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाते हैं।

उभरते क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार

आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज नवाचार और विकास को बढ़ावा दे सकती है:

- नवीकरणीय ऊर्जा: ऊर्जा की जरूरतों को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग करें।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था: बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्रों का लाभ उठाने के लिए ई-कॉमर्स, फिनटेक और डिजिटल बुनियादी ढांचे सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग को बढ़ावा दें।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करें।

लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना

मजबूत पारस्परिक संबंध बनाने से आपसी समझ और विश्वास बढ़ सकता है:

- सीमा हाटों का विस्तार: सीमा हाटों की संख्या बढ़ाएँ और जमीनी स्तर पर स्थानीय व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करें।
- सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए छात्रवृत्ति, संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम और सांस्कृतिक उत्सवों सहित सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दें।

नीति समन्वय को बढ़ाना

व्यापार समझौतों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मजबूत नीति समन्वय की आवश्यकता होती है:

- द्विपक्षीय व्यापार परिषद की स्थापना: व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की देखरेख करने और मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए सरकारों और निजी क्षेत्रों दोनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय व्यापार परिषद बनाएं।
- नियमित समीक्षा तंत्र: व्यापार समझौतों के प्रभाव का आकलन करने, चुनौतियों की पहचान करने और नीतियों और विनियमों में आवश्यक समायोजन करने के लिए नियमित समीक्षा तंत्र को लागू करें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौतों ने व्यापार की मात्रा को बढ़ाकर, जीडीपी वृद्धि को बढ़ाकर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करके और रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर दोनों देशों की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टैरिफ में कमी और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण ने व्यापार में पर्याप्त वृद्धि की है, जिससे कपड़ा, कृषि और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ हुआ है। व्यापार असंतुलन, गैर-टैरिफ बाधाओं और बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, आर्थिक सहयोग बढ़ाने

के अवसर अभी भी बहुत हैं। बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश, मानकों का सामंजस्य और बांग्लादेश से निर्यात को बढ़ावा देने से व्यापार संबंधों में और संतुलन आ सकता है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार, लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के साथ, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है। सार्क और बिम्सटेक जैसे ढांचे के माध्यम से प्रभावी नीति समन्वय और क्षेत्रीय सहयोग व्यापार समझौतों के लाभों को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण होगा। चूंकि भारत और बांग्लादेश अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत बना रहे हैं, इसलिए ये प्रयास अधिक संतुलित, मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित होगी।

संदर्भ

1. वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार। (विभिन्न रिपोर्ट)। [http://commerce.gov.in/]
2. बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो (बीबीएस)। (विभिन्न रिपोर्ट)। [http://bbs.gov.bd/]
3. विश्व बैंक। (2023)। विश्व विकास सूचकांक। [https://data.worldbank.org/]
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)। (2023)। भारत और बांग्लादेश पर देश रिपोर्ट। [https://www.imf.org/en/Countries]
5. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)। (2023) । व्यापार और विकास रिपोर्ट। [https://unctad.org/]
6. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)। (विभिन्न रिपोर्ट)। [https://www.rbi.org.in/]
7. बांग्लादेश बैंक। (विभिन्न रिपोर्ट) । [https://www.bb.org.bd/]
8. एशियाई विकास बैंक (एडीबी)। (2023)। आर्थिक संकेतक और आउटलुक रिपोर्ट। [https://www.adb.org/]
9. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), भारत। (विभिन्न सर्वेक्षण)। [http://mospi.nic.in/national-sample-survey-office-nsso]
10. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)। (2023)। रोजगार और श्रम सांख्यिकी। [https://www.ilo.org/]
11. वाणिज्य मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार। (विभिन्न रिपोर्ट)। [http://mincom.portal.gov.bd/]
12. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)। (2023)। व्यापार नीति समीक्षा। [https://www.wto.org/]
13. आर्थिक टाइम्स। (2023)। भारत-बांग्लादेश व्यापार पर रिपोर्ट। [https://economictimes.indiatimes.com/]
14. हिंदुस्तान टाइम्स। (2023) । द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर लेख। [https://www.hindustantimes.com/]
15. ढाका ट्रिब्यून। (2023)। बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि पर रिपोर्ट। [https://www.dhakatribune.com/]